[2007] 12 एस सी आर 884

संगम स्पिनर्स

बनाम

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -I

4 दिसंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे. जे.]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 - धारा 16 (1) (डी)-शैशवावस्था संरक्षण-नए स्थापित कारखानों के लिए, छूट के माध्यम से 3 वर्षों के लिए अधिनियम की प्रयोज्यता-छूट प्रावधान को छोड़ना। 1998 में पूर्वव्यापी प्रभाव से 22-9-1997-आयोजितः चूक चाहे जो भी हो, अपीलार्थी कारखाना, जो 1-9-1995 पर स्थापित किया गया था, स्थापना की तारीख से शुरू होने वाले पूरे 3 वर्षों के लिए सुरक्षा का हकदार है-सामान्य खंड अधिनियम 1897 — एस. 6 (सी)।

निरसन-उपार्जित अधिकार पर प्रभाव-सामान्य खंड अधिनियम 1897 धारा 6 (सी) - क़ानूनों की व्याख्या-पूर्वव्यापी या संभावित संचालन-निर्धारण-आयोजितः प्रत्येक कानून प्रथम दृष्टया संभावित है जब तक कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा उसका संचालन पूर्वव्यापी नहीं किया गया हो।

अपीलकर्ता कारखाना 1-9-1995 पर स्थापित किया गया था। नए कारखाने स्थापित किए गए स्थापना की तिथि। इस तरह के शैशव संरक्षण के लिए प्रावधान अर्थात खंड (घ) धारा 16 (1) इस अधिनियम को 1998 में क़ानून से हटा दिया गया था, लेकिन पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, 22-9-1997 से।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने माना कि एस को छोड़ना। 16(1) (घ) अधिनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, इसके तहत छूट का लाभ अपीलार्थी-कारखाने को उपलब्ध था केवल 22-9-1997 तक और उसके बाद नहीं। इस आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 . एस के खंड (सी) के संदर्भ में। 6 सामान्य खंडों का अधिनियम, 1897 जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, निरसन नहीं होगा निरस्त किए गए अधिनियम के तहत। में संशोधन का प्रभाव तत्काल मामला वही है। [पैरा 16] [891-सी]

1.2 . यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक कानून प्रथम दृष्टया संभावित है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से न हो पूर्वव्यापी संचालन के लिए निहितार्थ। लेकिन नियम में सामान्य लागू नहीं होता है जहाँ क़ानून का उद्देश्य प्रभावित करना है निहित अधिकार या नया बोझ डालना या मौजूदा बोझ को कम करना दायित्व। जब तक कि कानून

में दिखाने के लिए पर्याप्त शब्द न हों विधानमंडल का मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने का इरादा, यह माना जाता है केवल भावी होने के लिए 'नोवा कॉन्स्टिट्यूशियो फ्यूचरिस फॉर्मम इम्पोनेयर डेबेट नॉन प्रेटेराइटिस।' सामान्य नियम के एक तार्किक परिणाम के रूप में, उस पूर्वव्यापी संचालन को तब तक अभिप्रेत नहीं माना जाता है जब तक कि इरादा व्यक्त शब्दों या आवश्यक निहितार्थ से प्रकट होता है, इस प्रभाव के लिए एक अधीनस्थ नियम है कि एक क़ानून या एक धारा।

इसका इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसका पूर्वव्यापी संचालन बड़ा हो। इसकी भाषा आवश्यक बनाती है। दूसरे शब्दों में, ध्यान दें।

वैधानिक प्रावधान की भाषा के लिए भुगतान किया जाना चाहिए संसद द्वारा अभिप्रेत पूर्वव्यापीता के दायरे का निर्धारण करना। [पैरा 17] [891-डी, ई, जी; 892-ए]

केशवन माधवन मेमन बनाम। बॉम्बे राज्य, ए.आई.आर. (1951) एससी 128 ; दिल्ली क्लॉथ मिल्स एंड जनरल कंपनी लिमिटेड बनाम सी. आई. टी., दिल्ली एयर (1927) पी. सी. 242; अमीरेड्डी राजा गोपाल राव बनाम अमीरेड्डी सीतारामम्मा, ए.आई.आर. (1965) एससी 1970; भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह, ए.आई.आर. (1989) एससी (1933) ; जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम। श्री त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य, [1974] 1 एस. सी. सी. 19; अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम सी. आर. रंगधमैया

और अन्य, [1997] 6 एस. सी. सी 623 और एस. एल. श्रीनिवास जूट ट्वाइन मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, [2006] 2 एससीसी 740, पर भरोसा किया।

जयंतीलाल अमृतलाल बनाम भारत संघ और अन्य, ए.आई.आर. (1971) एससी 1193 ; गोविंददास और ओआरएस। वी. आयकर अधिकारी और अन्य, ए.आई.आर. (1977) संगम स्पिनर्स बनाम क्षेत्रीय लाभ निधि 885 आयुक्त-I एससी 552 और मैजिक वॉश इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम सहायक भविष्य निधि आयुक्त, पणजी और अन्य, (1999) Lab.I.C. 2197, संदर्भित। रीड वी। रीड, (1886) 31 Ch D 402, का उल्लेख किया गया है।

"न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत (दसवां संस्करण, 2006), संदर्भित।

2. अपीलार्थी उस अवधि के लिए संरक्षण का हकदार होगा। स्थापना की तारीख से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए इस तरह के शैशवावस्था संरक्षण के प्रावधान के निरसन के बावजूद। [पैरा 20] [892-ई]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1785/2001

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 29.11.2000 से, जो कि 2000 की डी. बी. विशेष अपील सं. 1150 में पारित किया गया।

डॉ. मनीष सिंघवी, पी. वी. योगेश्वरन और अशोक के. महाजन अपीलार्थी की ओर से।

एस. वसीम ए. कादरी, डी. एस. माहरा और बी. वी. बलराम दास उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. इस अपील में चुनौती है राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिया गया निर्णय जोधपुर ने अपीलार्थी द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज कर दिया। चुनौती विशेष अपील में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के लिए था जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का निर्णय (संक्षेप में ' आयुक्त ')। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कर्मचारियों की धारा 16 (1) (डी)भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) था। 1998 के अधिनियम No.10 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ क़ानून से हटा दिया गया अर्थात 22.9.1997 से। दूसरे शब्दों में, यह माना गया था कि शिशु संरक्षण 22.9.1997 के बाद अपीलार्थी कारखाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

2. तथ्यात्मक परिदृश्य एक बहुत ही संकीर्ण दिशा-निर्देश में निहित है। अपीलार्थी आई. डी. 1 पर उत्पादन शुरू किया और इसके अनुसार, यह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2007] 12 एस. सी. आर. का हकदार था। उस दिन से अधिनियम की धारा 16 (1) (डी) के तहत लाभ। अगस्त से 1998

अपीलार्थी ने अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना शुरू कर दिया क्योंक अधिनियम की धारा 16 (1) (डी) के तहत परिकल्पित तीन साल की अवधि समाप्त हो गया। 26.3.1999 पर अधिनियम की धारा 7ए के तहत जांच की गई थी। सितंबर, 1995 से अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया जुलाई, 1998। दिनांक 27.7.2000 के आदेश से आयुक्त ने एक विशिष्ट निष्कर्ष कि कंपनी एक नई इकाई थी और इसके लिए पात्र थी अधिनियम की धारा 16 (1) (डी) के तहत छूट लेकिन चूंकि इसे समाप्त कर दिया गया था मूर्ति से 22.9.1997 लाभ उस तारीख तक उपलब्ध था और नहीं इसके बाद। दायर की गई रिट याचिका को विद्वान एकल द्वारा खारिज कर दिया गया था न्यायाधीश, विशेष अपील भी ऐसी ही थी।

3. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण असमर्थनीय है और भले ही पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया हो, यह किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना था अपीलार्थी का हक।

4. दूसरी ओर प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील ने समर्थन किया आयुक्त और उच्च न्यायालय के आदेश।

5. अलग-अलग समय पर धारा 16 की स्थिति इस प्रकार हो सकती है, मूल रूप से अधिनियमित धारा 16 इस प्रकार हैः

"16. सरकारी या स्थानीय कारखानों पर लागू नहीं होने वाला अधिनियम प्राधिकरण और शिशु कारखानों के लिए भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा-

(क) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित कोई कारखाना, और

(ख) इससे पहले या बाद में स्थापित कोई अन्य कारखाना

जब तक कि इनकी स्थापना को तीन वर्ष बीत न जाएं।"

6. कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा धारा 16 में संशोधन किया गया था। (संशोधन) अधिनियम, 1958 और प्राचार्य की धारा 16 की उप-धारा (1) अधिनियम को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया थाः

"(1) यह अधिनियम किसी भी प्रतिष्ठान पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि उस तारीख से तीन साल की तारीख जिस पर प्रतिष्ठान है, या है स्थापित किया गया।

व्याख्याः सन्देह दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी प्रतिष्ठान को केवल उसके स्थान में परिवर्तन के कारण नया स्थापित नहीं माना जाएगा।

7. धारा 16 (1) को एक बार फिर कर्मचारियों द्वारा संशोधित किया गया था। पहचान निधि (संशोधन) अधिनियम, 1960 और धारा की उप-धारा (1) जैसा कि नीचे दिया गया हैः

"(1) यह अधिनियम लागू नहीं होगाः

(क) सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान को अधिनियम, 1912, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी राज्य, जो इससे कम रोजगार देता हो पचास व्यक्ति और शक्ति की सहायता के बिना काम कर रहे हैं; या

(ख) पचास या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले किसी अन्य प्रतिष्ठान के लिए या बीस या उससे अधिक लेकिन पचास से कम व्यक्ति तीन की समाप्ति तक पूर्व के मामले में वर्ष और के मामले में पाँच वर्ष उत्तरार्द्ध, उस तारीख से जिस पर प्रतिष्ठान है, या रहा है, स्थापित करें।

व्याख्याः शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी प्रतिष्ठान को केवल नया स्थापित नहीं माना जाएगा। इसके स्थान में परिवर्तन के कारण।"

8. कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा धारा 16 में और संशोधन किया गया। विविध (संशोधन) अधिनियम, 1988 से प्रभावी (ख), (ग) और (घ) और धारा 16 में उक्त संशोधन इस प्रकार है -:

"(ख) नियंत्रण में या उससे संबंधित किसी अन्य प्रतिष्ठान के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार और जिसका कर्मचारी किसी भी योजना या नियम के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लाभ; या अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभ के हकदार हैं।

(ग) किसी भी केंद्रीय प्रांतीय के तहत स्थापित किसी अन्य प्रतिष्ठान को या राज्य अधिनियम और जिनके कर्मचारी इसके लाभों के हकदार हैं अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के अनुसार ऐसे लाभों को नियंत्रित करने वाली उस अधिनियम के तहत बनाई गई कोई योजना या नियम; या

(घ) नव स्थापित किसी अन्य प्रतिष्ठान के लिए, जब तक कि ऐसी स्थापना की तारीख से तीन साल की अवधि है, या स्थापित किया गया है।"

9. इसके बाद, धारा 16 को कर्मचारियों द्वारा फिर से संशोधित किया गया। भविष्य निधि और विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 1988 धारा 16 की उप-धारा (1) में स्पष्टीकरण के साथ खंड (घ) को हटाना 22.9.1997 से प्रभाव। (उक्त चूक शुरू में द्वारा की गई थी अध्यादेश No.17/1997 को 22.9.1997 पर जारी किया गया जिसके बाद अध्यादेश No.25/1997 दिनांक 25.12.1997 और अध्यादेश संख्या 8 1998 दिनांक 23.4.1998 के बाद 1998 का अधिनियम 10)

10. अपीलार्थियों के अनुसार, खंड (घ) के तहत 1988 में संशोधन के बाद जो गैर-संशोधित प्रावधान थे, वे उनके मामलों पर लागू होते हैं। और वे गैर-आवेदन के संबंध में सुरक्षा के हकदार थे उस तारीख से 3 साल की अवधि के लिए अधिनियम जिस दिन ऐसी स्थापना की जाती है। स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, खंड (डी) के साथ हटा दिया

गया था 22.9.1997 से प्रभावी, यह अधिनियम प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू था और इससे कोई छूट या 'शैशवावस्था' उपलब्ध नहीं थी।

11. इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न संशोधन का प्रभाव है।

12. जयंतीलाल अमृतलाल बनाम भारत संघ और अन्य, (1971) एस. सी. 1193, इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

"यह देखने के लिए कि क्या निरस्त के तहत अधिकार और देनदारिया नए अधिनियम द्वार कानून को समाप्त कर दिया गया है, उचित दृष्टिकोण यह पूछताछ करने के लिए नहीं है कि क्या नए अधिनियम में इसकी नई व्यवस्था है। निरस्त प्रावधानों के तहत अधिकारों और देनदारियों को जीवित रखा कानून लेकिन क्या इसने उन अधिकारों और देनदारियों को छीन लिया है। अधिकारों का संरक्षण करने वाले नए अधिनियम में बचत खंड का अभाव और दोहराए गए कानून के तहत देनदारियां न तो भौतिक हैं और न ही निर्णायक।

सवाल का जवाब "13. गोविंददास और अन्य बनाम आयकर अधिकारी और अन्य 1977 एस. सी. 552 में यह निर्धारित किया गया था किः

"अब यह समय द्वारा पवित्र व्याख्या का अच्छी तरह से स्थापित नियम है और न्यायिक निर्णयों द्वारा पवित्र किया गया है कि जब तक कि एक क़ानून की शर्तें स्पष्ट रूप से प्रदान करें या आवश्यक रूप से इसकी

आवश्यकता है, पूर्वव्यापी किसी कानून को इस तरह से लागू नहीं किया जाना चाहिए कि उसे हटा दिया जाए या प्रक्रिया के मामलों के संबंध में अन्यथा दायित्व। द. सामान्य-नियम जैसा कि हैल्सबरी ने खंड में कहा है। 36 कानूनों का इंग्लैंड का (तीसरा संस्करण) और कई निर्णयों में दोहराया गया। इस न्यायालय के साथ-साथ अंग्रेजी न्यायालयों का कहना है कि इसके अलावा अन्य सभी कानून जो केवल घोषणात्मक हैं या जो केवल मामलों से संबंधित हैं

प्रक्रिया या साक्ष्य प्रथम दृष्टया संभावित हैं और किसी कानून को पूर्वव्यापी संचालन नहीं दिया जाना चाहिए ताकि किसी मौजूदा अधिकार को प्रभावित करना, बदलना या नष्ट करना या कोई नया दायित्व बनाना या दायित्व जब तक कि उस प्रभाव को किए बिना टाला नहीं जा सकता है अधिनियम की भाषा पर हिंसा। यदि अधिनियम है ऐसी भाषा में व्यक्त किया गया जो या तो काफी सक्षम है व्याख्या में, इसे केवल संभावित के रूप में माना जाना चाहिए।

14. बंबई उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इस पर विचार करते हुए 16 (1) (डी) में संशोधन से शैशवावस्था में कटौती मैजिक वॉश इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम में इस प्रकार आयोजित 3 वर्षों के लिए, स्थायी भविष्य निधि आयुक्त, पणजी और अन्य, (1999) आई. सी. 2197:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके तहत निहित अधिकार या कानून को कानून द्वारा पूर्वव्यापी रूप से हटाया जा सकता है, लेकिन तब ऐसे

अधिकारों या लाभों को छीनने वाले क़ानून को उस प्रभाव के लिए अपने इरादे को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। बाल्यावस्था से पहले की अवधि संशोधित प्रावधान धारा 16 (1) (घ) के मामले में पाँच वर्ष था - 20 से 50 श्रमिकों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान और इस शैशवावस्था लाभ को वापस लेने की स्थिति में, यह आवश्यक था कि विधानमंडल का इरादा [2007] 12 एस. सी. आर. में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट स्वयं संशोधित प्रावधान है कि अधिकार और लाभ जिनके पास थे पहले से ही उपार्जित वापस ले लिया गया। संशोधित खंड 16 (1) (घ) भारत के राष्ट्रपति द्वारा लेकिन संशोधित धारा 16 रखी गई थी केवल 1 अगस्त, 1988 से प्रभावी, जो केंद्र सरकार को अलग-अलग तिथियां निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। हम इसे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का लागू होना पाते हैं। इन परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि विधायिका का आशय शैशवावस्था का लाभ छीनना था जो मौजूदा प्रतिष्ठानों को पहले ही यह लाभ मिल चुका था द्वारा स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा नहीं लिया गया है संशोधित प्रावधान धारा 16 (1) (डी)। इन परिस्थितियों में हमइस राय के लिए कि याचिकाकर्ता की शैशवावस्था लाभ के लिए 26 मई, 1986 से प्रभावी पांच साल की अवधि नहीं ली गई है।

अधिनियम की धारा (1) (डी) के संशोधित प्रावधान द्वारा; औरयाचिकाकर्ता उक्त शैशवावस्था लाभ का आनंद लेना जारी रख सकता है मई, 1991 तक पाँच वर्ष की अवधि। इसलिए की गई थी मांग प्रत्यर्थी 1 द्वारा मई, 1991 तक की अवधि के लिए निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता प्रावधानों का पालन कर रहे हैं जून, 1991 से प्रभावी अधिनियम।

15. इस मामले को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। की धारा 6 परिधीय खंड अधिनियम, 1897 (संक्षेप में 'सामान्य खंड अधिनियम')निरसन का प्रभाव। अब तक प्रासंगिक उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

"6. निरसन का प्रभाव - जहां यह अधिनियम, या कोई (केंद्रीय अधिनियम) या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया विनियमन, किसी भी अब तक या इसके बाद किया जाने वाला अधिनियम, तब, जब तक किअलग इरादा दिखाई देता है, निरसन नहीं होगा–

(क) किसी भी ऐसी चीज को पुनर्जीवित करें जो उस समय लागू या मौजूद न हो, निरसन प्रभावी होता है; या

(ख) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित करता है या उसके तहत विधिवत किया गया या पीड़ित कुछ भी; या

(ग) अर्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है, इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के तहत उपार्जित या उपगत; या

(घ) इस प्रकार निरस्त किसी भी अधिनियम के विरुद्ध किया गया अपराध के संबंध में किए गए किसी भी दंड, ज़ब्त या सजा को प्रभावित करता है।

(ई) संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है। ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ज़ब्त या सजा; या दंड इस प्रकार लगाया जा सकता है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था।"

16. ऊपर उद्धृत धारा 6 के खंड (ग) के संदर्भ में, जब तक कि अलग इरादा प्रतीत होता है कि निरसन किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार को प्रभावित नहीं करेगा या अधिनियमन निरसन के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित दायित्व। द. तत्काल मामले में संशोधन का प्रभाव समान है।

17. यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक क़ानून प्रथम है। जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी संचालन के लिए आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं किया जाता है (केशवन माधवन मेमन बनाम बॉम्बे राज्य, AIR (1951) SC 128 देखें।) लेकिन सामान्य रूप से नियम नहीं है लागू होता है जहां क़ानून का उद्देश्य निहित अधिकारों को प्रभावित करना है या विधानमंडल के इरादे को दिखाने के लिए कानून में शब्द पर्याप्त हैं -

मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है, इसे केवल संभावित माना जाता है फ्यूचरिस फॉर्मम इम्पोनेरे डेबेट नॉन प्रेटेराइटिस '। प्रभु के शब्दों में "ब्लैनेसबर्ग", प्रावधान जो पारित होने पर अस्तित्व में एक अधिकार को छूते हैं स्पष्ट अधिनियमन या आवश्यक इरादे के अभाव में क़ानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। (दिल्ली क्लॉथ मिल्स और जनरल कं. लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. दिल्ली ए. आई. आर. (1927) पी. सी. 242)। प्रत्येक कानून, यह मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित अधिकार, या एक नया दायित्व बनाता है या एक नया कर्तव्य लगाता है, या लेनदेन के संबंध में एक नई अक्षमता जोड़ता है। पहले से ही अतीत, एक पूर्वव्यापी नहीं होने का इरादा माना जाना चाहिए प्रभाव। (अमीरेड्डी राजा गोपाल राव बनाम अमीरेड्डी सीतारामम्मा, ए.आई.आर. (1965) एससी 1970 देखें।) सामान्य नियम के एक तार्किक परिणाम के रूप में, उस पूर्वव्यापी संचालन को तब तक अभिप्रेत नहीं माना जाता है जब तक कि वह इरादा नहीं है, व्यक्त शब्दों या आवश्यक निहितार्थ से प्रकट होने पर, एक है।

अधीनस्थ नियम इस प्रभाव के लिए कि कोई क़ानून या उसमें कोई धारा नहीं होनी चाहिए अपनी भाषा की तुलना में बड़े पूर्वव्यापी संचालन के रूप में माना जाता शब्दों को वैधानिक भाषा पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। द्वारा अभिप्रेत पूर्वव्यापीता के दायरे को निर्धारित करने के लिए प्रावधान संसद। (भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह, ए.आई.आर. (1989)

एससी 1933) उपरोक्त स्थिति को "वैधानिक सिद्धांतों" में उजागर किया गया है।

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह की व्याख्या (पीपी में दसवां संस्करण, 2006, 474 और 475)

18. जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम श्री त्रिलोकी नाथ खोसा और अन्य, [1974] 1 एस. सी. सी. 19 और अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और ओआरएस। वी. सी. आर. रंगधमैया और अन्य, [1997] 6 एस. सी. सी. 623, यह न्यायालय वह प्रावधान जो केवल भविष्य के अधिकारों को प्रभावित करने के लिए संचालित होता है उन लाभों या अधिकारों को प्रभावित करना जो पहले से ही अर्जित या आनंदित हैं, जब तक कि विलोपन, संचालन में पूर्वव्यापी नहीं है।

19. उपरोक्त स्थिति को इस अदालत द्वारा एस. एल. में उजागर किया गया था। श्रीनिवास जूट ट्वाइन मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, [2006] 2 एससीसी 740।

20. कानून में उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, के निर्णय आयुक्त और उच्च न्यायालय अक्षम्य हैं और उन्हें अलग कर दिया जाता है। द.अपीलार्थी तीन वर्ष की अवधि के लिए संरक्षण का हकदार होगा। स्थापना की स्थापना की तारीख से शुरू होने के बावजूद इस तरह के शैशवावस्था संरक्षण के प्रावधान का निरसन।

21. अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

बी. बी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विशाल व्यास (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: *यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।*